भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3004

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना

3004. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (केएलआईपी) का उद्घाटन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और इसकी संपूर्ण लागत का वित्तपोषण करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और इसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है तथा इससे कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है और इस परियोजना के संचालन हेतु शेष कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) तेलंगाना राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, माननीय मुख्य मंत्री तेलंगाना सरकार द्वारा जयाशंदकर-भुल्लापेल्लई जिले में मेडीगड्डा में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (केएलआईपी) के अंतर्गत बैराज की शुरूआत की गई तथा दिनांक 21.06.2019 को कन्नेपल्ल में परियोजना के अंतर्गत एक पंप हाउस का उद्घाटन किया गया।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, माननीय मुख्य मंत्री तेलंगाना सरकार के दिनांक 11.02.2016 के पत्र के माध्यम से यह अनुरोध किया गया कि कालेश्वरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की मान्यता दी जाए। हालांकि, राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार की उच्च अधिकार प्राप्त स्टीयरिंग कमेटी (एचपीएससी) के विचार हेतु तेलंगाना राज्य सरकार से निर्धारित प्रोफॉर्मा में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

तेलंगाना सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जून, 2019 तक इस परियोजना पर कुल 50481.60 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं। यह परियोजना पूरी तरह से राज्य के फंड पर आधारित है। इस परियोजना में हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी सहित राज्य के 15 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में इस परियोजना की बकाया लागत 30,000 करोड़ रूपए परिकल्पित किए गए हैं।

*****